भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान

4054. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भोपाल जिले की हुजूर तहसील के अन्तर्गत नवी बाग ग्राम में कुछ भूमि "भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान" के लिए अर्जित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी भूमि किस भाव पर अर्जित की गई है ;

(ग) क्या इस भूमि के लिए मुआवजा बाजार दर पर दिया गया है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार उन किसानों के, जिनकी भूमि अर्जित की गई है, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने जिला भोपाल के तहसील हुजूर में नबी बाग ग्राम में 50 हैक्टर जमीन 53.5 लाख रु० की अधिग्रहीत की और भा० कृ० अ० परिषद को भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए दे दी।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की है उन्हें नियमों के अनुसार मुआवजा दिया गया है।

(घ) भारत सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया कि जिन किसानों की जमीन खरीदी गई है उनके परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाएगा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलहनों का मूल्य

4055. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तिलहनों का मूल्य निर्धारित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्यवार तिलहनों की अलग-अलग किस्मों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित करने के वास्ते कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) छिलके सहित मूंगफली, रेपसीड-सरसों, सोयाबीन (काली तथा पीली किस्में) सूरजमुखी, कुसुम और खोपरा जैसे मुख्य तिलहनों का सरकार की कृषि मूल्य नीति के अन्तर्गत लाया जा रहा है। तदनुसार, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर मौसम में इन तिलहनों के समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। हर वर्ष तोरिया और रेपसीड-सरसों के मूल्य के अन्तर के आधार पर तोरिया का समर्थन मूल्य भी घोषित किया जाता है।

(ग) सभी राज्यों के लिए लागू एक समान आधार पर रबी और खरीफ तिलहनों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम पहले ही विद्यमान है।

फसल बीमा योजना

4056. **श्री लक्खीराम अग्रवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सभी राज्यों में फसल बीमा योजना को लागू करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों को इस आशय के कोई अनुदेश जारी किये गये हैं या करने का विचार है कि फसलों को कोई नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा, निर्धारित समय सीमा के भीतर दे दिया जाना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वृहत फसल बीमा योजना एक स्वैच्छिक योजना है। सभी राज्य संघ शासित प्रदेश किसी क्षेत्र में इसका कार्यान्वयन करके इसके पक्ष में विकल्प देने के लिए स्वतंत्र हैं। इस समय सभी राज्यों संघ शासित प्रदेशों में अनिवार्य रूप से वृहत फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

रासायनिक उर्वरकों का मानव जीवन पर असर

4057. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक उर्वरकों का कृषि में इस्तेमाल किये जाने का मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए नये कीटनाशक बनाए गए हैं जो पौधों पर आधारित हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में नीम के वृक्ष और उसकी गिरी का इस्तेमाल बहुत सफल रहा है और यह भी कि देश में पर्यावरण और जलवायु संबंधी स्थितियों नीम के वृक्ष लगाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए नीम की गिरी का कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किये जाने को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) नई और अपेक्षाकृत सुरक्षित कृमि नाशी दवाइयों, पौधों पर आधारित वनस्पति विज्ञान मूल की) कृमिनाशी दवाओं सहित, के विकास पर अनुसंधान एक सतत प्रक्रिया है जो विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया जाता है। इन जांचों के माध्यम से नीम, तम्बाकू, आदि जैसे पौधों पर आधारित कृमि नाशी दवाइयां विकसित की गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने नीम पर आधारित कृमिनाशी दवाइयों के निर्माण और उपयोग को कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत किया है।

Production of oil seeds

4058. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the comparative percentage of rise in the cultivation and production of oil seeds in the country during 1989, 1990 and 1991;

(b) what is the present area under oil-seeds cultivation in the country and what percentage it constitutes of the total cultivable loan;

(c) what was the gap between the projection and the actual production of oil-seeds during 1989, 1990 and 1991 and what are the reason for the shortfall in the estimated targets;

(d) what are the achievements made in the production of oil-seeds due to incentives, if any, given by Government for brining improvement in production, area-wise; and

(e) what measures are contemplated by Government to attain self-sufficiency in oil-seeds?